



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 470]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 1975/कार्तिक 28, 1897

No. 470]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 1975/KARTIKA 28, 1897

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 19th November 1975

S.O. 658(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies, No. S.O. 669(E)/18/FB/IDRA/74, dated the 20th November, 1974 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments, entered into before the 4th day of May, 1972, and in force immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette and relating to banks and financial institutions, to which the industrial undertaking known as Smith, Stanistreet and Company Limited, Calcutta, or the company owning such undertaking is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year from the date of publication of the said Order in the Official Gazette and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended by a further period up to and inclusive of the 3rd of May, 1976;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period up to and inclusive of the 3rd of May, 1976.

[No. F. 4/2/72-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1975

का० आ० 658 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 669 (अ)/18/चख/उ० वि० वि० अ०/74. तारीख 20 नवम्बर, 1974 द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषित किया है कि 4 मई, 1972 से पूर्व की गई और राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन से ठीक पूर्व प्रवृत्त तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से सम्बद्ध सभी सविदाओं, सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, समझौतों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का, जिनका, स्मिथ, स्टेटस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के नाम से ज्ञात उपक्रम या ऐसे उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हों, प्रवर्तन राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि पर्यन्त निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं तथा दायित्व उक्त अवधि पर्यन्त निलम्बित रहेंगे ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 3 मई, 1976 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, बढ़ाई जानी चाहिए,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 3 मई, 1976 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए बढ़ाती है।

[सं० का० 4/2/72-सी०यू०सी०]

दिनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव।